include instructions to administrative Ministries/Departments and public sector enterprises to set up Management Boards/Empowered Committees for expeditious finalisation of contracts and release of funds matching with physical progress.

सचिवों की समिति का प्रतिवेदन :

1762. श्री वीरेन जे० शाह :

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग और प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रतिवेदन कब प्राप्त किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि समिति ने अपने प्रतिवेदन में दोनों विभागों को बंद करने की सिफारिश की है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त करने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) :

(क) से (च) सचिवों की समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को जारी रखने अथवा न रखने के मुद्दे पर विचार कर रही है । इस स्थिति में अभी इस विचारणा को स्पष्ट करना जनहित में नहीं होगा।

Special Assistance for Immigrating Population in Bombay

1763. SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL : Will the MINISTER OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether Government of Maharashtra has requested for special assistance for infrastructural civic facilities for the immigrating population from outside the State to the city of Bombay; and

(b) if so, the details of the decision of the Planning Commission thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) An amount of Rs. 50 crores has been provided for the problems of Bombay city, within the overall allocation of formula-based Central assistance in the Annual Plan of the State for 1992-93. Additional Rs. 20 crores of Central assistance has also been agreed for Bombay as mega city during the current year.

Contradictory Criteria for Financial Assistance for Anti Poverty Programme

1764. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the MINISTER OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Planning Commission and previous Finance Commissions have adopted Contradictory Criteria for giving Financial assistance for anti poverty programmes and to meet non-plan deficit;

(b) whether there is any proposal to rationalise the criteria; and

(c) if so, what are the details thereof ?